524

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–22)

GSM (M-I)-2422

निर्धारित समय: तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	अधिकतम अंक: 250 *Maximum Marks: 250*

Name: Ritik Arya **Mobile Number:**

Medium (English/Hindi): HINDI **Reg. Number:** 3094

Center & Date: M.N, 06/09/24 **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*****:** 0808386

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH.***

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए ***(To be filled by Evaluator only)***

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

drishti | दृष्टि The Vision

1. न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रत्याभूति लोकतंत्र के अस्तित्व का मूल है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional guarantee of judicial independence is fundamental to the existence of a democracy. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत मे शक्ति का पृथक्करण अपनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान मे अनु. 124 से शुरू होता है न्यायालय की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है

लोकतंत्र के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और संवैधानिक प्रावधान

→ न्यायालय को (SC को) संविधान का रक्षक कहा गया है

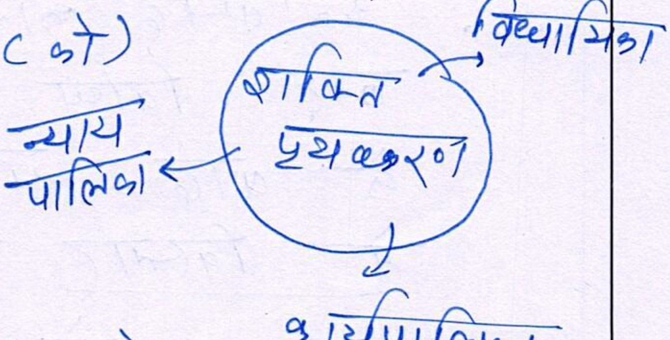

→ SC के सदस्यों को विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है।

→ अनु. 32 तथा अनु. 226 द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा हाइकोर्ट अधिकारों के रक्षक है

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ वर्तमान मे कॉलेजियम प्रणाली (थर्ड जजेस केस के बाद) न्यायालय मे कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कम करके पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाए रखती।

→ संसद न्यायालय पर तथा न्यायालय संसद की कार्यवाही मे दखल नहीं दे सकता (अनु. 121 & अनु. 122)

→ केशवानंद भारती वाद (1973) के बाद विधि की उचित प्रक्रिया के बाद न्याया. की शक्ति मे विस्तार हुआ है।

→ संविधान मे न्यायधीशो के वेतन का भार संचित निधि पर है जिससे कार्यपालिका कटौती न कर सके।

अतः सफल लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है न्यायालय को न्यायिक सक्रियता से बचते हुए न्यायिक संयम द्वारा कार्य करना चाहिए।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) भारत में हाशिये पर स्थित समुदायों को निशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का प्रभावी अंतरण सुनिश्चित करता है। संपुष्ट कीजिये। (150 शब्द) 10

The National Legal Services Authority (NALSA) ensures the effective delivery of free legal aid services to marginalized communities in India. Substantiate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत मे संविधान मे सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट व जिला कोर्ट की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक न्याय के लिए नालसा की स्थापना की गई।

→ 1987 → राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम

→ यह निशुल्क न्याय (अनु. 39)

→ लोक अदालत

→ सुप्रीम कोर्ट के न्याया. के अन्तर्गत कार्य इसके अतिरिक्त राज्य मे हाइकोर्ट के जज

← यह समाज के वंचित वर्ग यथा SC, ST, महिलाऐ, अल्पसंख्यक के लिए निशुल्क न्याय

↳ यह इन्हे वकील उपलब्ध करवाता तथा शुल्क को शून्य या न्यून करता।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सकारात्मक पक्ष

→ निदेशक तत्व को लागू

→ अनु. 21 सभी को न्याय के अनुरूप

→ 5 करोड़ केस पेंडिंग (नेशनल डाटा ग्रिड) मे सहायक

↳ यह वैकल्पिक मंच प्रदान करता

→ समाज के कमजोर वर्ग जो महंगे न्याय को नही अपना सकते उनके लिए सहायक तथा सामाजिक कल्याण की स्थापना

→ लोक अदालत मध्यस्थता द्वारा हाशिए पर स्थित लोगो की सहायता

इसके अतिरिक्त कुछ चुनौतियाँ

① प्रकृति: आत मे अच्छी तरह से लागू नहीं

② वकीलों का अभाव

③ SC/ST को जानकारी का अभाव

④ राज्य व केन्द्र मे संपर्क सही नहीं

अत: नालसा वैकल्पिक न्याय का बढ़िया माध्यम हो सकता है तथा सामाजिक न्याय मे अग्रणी भूमिका निभा सकता।

3. भारत में राज्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को पर्याप्त कार्यात्मक और वित्तीय सशक्तीकरण प्रदान करने में असहयोगशील प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

States in India appear unwilling to grant Panchayati Raj Institutions (PRIs) adequate functional and financial empowerment. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

गांधी के ग्राम स्वराज्य व निदेशक तत्व 40 के सपने को साकार करने के लिए 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई।

प्रावधान
1. त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना
2. ग्राम सभा को 29 विषय
3. सामाजिक न्याय
   - SC/ST
   - महिला आरक्षण → 33%
4. योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू

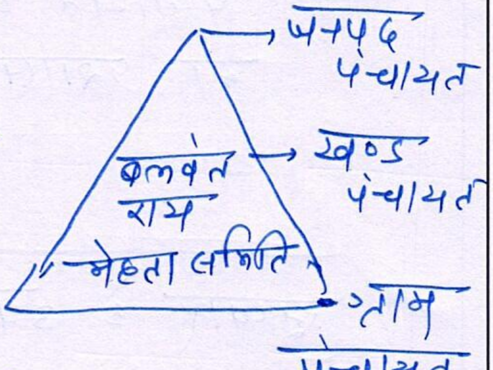

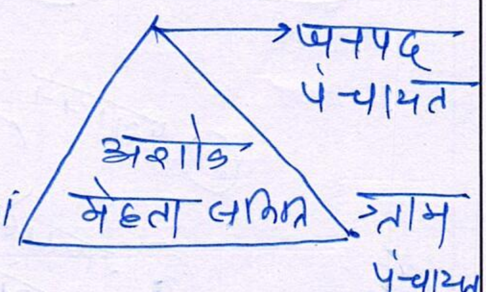

परंतु देखा गया कि पंचायतें कार्यात्मक और वित्तीय समस्या से जूझ रही हैं राज्यों द्वारा अभी भी

उन्हें स्वतंत्र इकाई न मानकर अपने अधीनस्थ इकाई समझा जाता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- कार्यात्मक चुनौती
  - → DM में शक्ति का केन्द्रीकरण
  - → पंचायत की खुद का प्रशासन नहीं

- वित्तीय सशक्तीकरण में चुनौती
  - → अनुदान पर निर्भर
  - → कर लगाने की शक्ति का विस्तार नहीं

सुधार के उपाय → पार्थ मैथ्यूज तथा सरकारिया आयोग ने इनके 3'F' की चुनौती को दूर करने के लिए सुझाव दिए —

1. प्रशासन का विकेन्द्रीकरण
2. राज्य के विषयों का हस्तांतरण
3. चुनाव समय पर
4. पर्याप्त वित्त

अतः वर्तमान में पंचायती राज भारत के 2047 तक विकसित बनने के स्वप्न का आधार बन सकते हैं।

drishti | दृष्टि The Vision

4. संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश तथा भारतीय दृष्टिकोण में समानताएँ और विभिन्नताएँ दोनों ही देखने को मिलती हैं। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

The British and Indian approaches to parliamentary sovereignty exhibit both similarities and differences. Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत मे शासन व संविधान का स्वरूप ब्रिटिश से काफी प्रभावित रहा है इसके बावजूद ब्रिटिशों ने संसदीय संप्रभुता तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता को त्याग दिया।

दोनों मे संसदीय संप्रभुता मे

समानता :-

- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया
- प्रधानमंत्री, संसदीय व्यवस्था न कि अमेरिका की तरह अध्यक्षीय
- बहुदलीय प्रतिस्पर्धीय प्रणाली
  जैसे → भारत → कांग्रेस, भाजपा, आप; ब्रिटेन → लेबर, कन्ज़र्वेटिव
- संसद को संविधान संशोधन की शक्ति

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- कार्यपालिका का निर्माण संसद सदस्य से।
- अध्यक्ष का पद, समितियों का निर्माण
- दो सदन
  - → भारत
    - LS
    - RS
  - → ब्रिटेन
    - लार्डसभा
    - ~~कॉमन~~ सदन

असमानताएँ
- → ब्रिटेन → संसदीय सर्वोच्चता
- → भारत → संविधान सर्वोच्चता

- वहाँ राजतंत्र है जबकि भारत में गणतंत्र
- वहाँ अध्यक्ष चुनने के बाद त्यागपत्र भारत में दल में बना रहता।
- ब्रिटेन में विपक्ष में शैडो कैबिनेट का प्रावधान भारत में नहीं
- संविधान के आधार पर ही भारत में शासन तथा न्यायालय का संसद पर प्रतिबंध जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च।
- अतः भिन्नताओं के बावजूद भारत का प्रशासन ब्रिटेन से प्रभावित रहा है।

5. राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी विधायी कार्य में शिष्टाचार और अपक्षपात के सातत्य के साथ-साथ सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये ज़िम्मेदार होते हैं। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द) 10

State legislature presiding officers are responsible for upholding decorum and impartiality in legislative work, as well as facilitating sound democratic practices. Explain. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत मे संसदीय व्यवस्था अपनायी गयी है यहाँ विविधता के साथ संघवाद पाया जाता है जहाँ शक्तियो का विभाजन किया गया है और राज्य एक स्वतंत्र इकाई है

ऐसे मे राज्य विधानमण्डल मे पीठासीन अधिकारी के निम्न कार्य →

- सदन का डेकोरम बनाए रखना तथा कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाना
- विपक्ष के नेताओं को समान समय देना
- विधेयक पास मे तटस्थता व पारदर्शिता
- दल बदल कानून को लागू करते समय निष्पक्षता |

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(वर्तमान मे आलोचनाएँ)

- दल बदल के लिए निर्णय न देना जैसा महाराष्ट्र मे देखने को मिला
- विपक्षी सांसदो को सदन से निष्कासन जैसा- झारखण्ड मे हुआ
- दल बदल के समय अपनी पार्टी या अपने समूह को फायदा जैसा → शिवसेना, महाराष्ट्र मामले मे हुआ
- विधेयको को नोटिस चढ़ाकर विपक्ष के विरोध के बाद ध्वनि मत से पास कर देना

सुधार → (1) सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन वाद मे अध्यक्ष की कार्यवाही को न्यायिक पुनरावलोकन

(2) ब्रिटेन अध्यक्ष की तरह दल से इस्तीफा दे देना चाहिए।

(3) दल बदल के समय एक निश्चित समय मे सभा बुलाना

अतः स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पीठासीन अधिकारी को निष्पक्ष व तटस्थ रहना चाहिए।

6. भारत के विकास में एक बड़ी चुनौती मानव संसाधन विकास पर अपर्याप्त ध्यान देना है। इस अपर्याप्तता को दूर करने संबंधी उपायों के सुझाव प्रदान कीजिये। (150 शब्द) 10

A major challenge in India's development is the insufficient focus on human resource development. Suggest measures to address this inadequacy. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत आज बड़ी जनसंख्या मे दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या है यहां 15-35 वर्ष के 65 करोड़ युवा है।

भारत वर्तमान मे अपनी जनसांख्यिकी लाभांश के चक्र से गुजर रहा है।

ऐसे मे भारत मे मानव संसाधन को लेकर चुनौती

(1) असंगठित क्षेत्र मे रोजगार ज्यादा (90%)

(2) महिला श्रम भागीदारी हर ग्लोबल (47%) से कम → 37%

(3) रोजगार की समस्या (वर्ल्ड बैंक 50.3% शिक्षित बेरोजगार)

(4) कृषि मे प्रच्छन्न बेरोजगारी
↳ 46% जनसंख्या निर्भर और जीडीपी योगदान 17%

drishti | दृष्टि The Vision

(5) कौशल आधारित संसाधन का अभाव

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

उपाय / सुझाव

→ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन, स्टार्ट अप इण्डिया जैसी योजनाओं का विस्तार

→ विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार चूँकि ये रोजगार गहन क्षेत्र है चीन, इण्डोनेशिया, वियतनाम पहले ही कृषि से विनिर्माण पर आ गए।

→ व्यावसायिक शिक्षा, AI, मशीनलर्निंग का प्रयोग (NEP-2020 में सिफारिश)

→ डिजिटल इण्डिया द्वारा फिनटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहन

अतः भारत की 5 ट्रिलियन इकोनोमी तथा 2047 तक के विकसित भारत बनने का आधार उसका मानव संसाधन है।

7. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रमुख बाज़ार स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The Competition Commission of India plays a crucial role in preventing the misuse of dominant market positions by multinational companies in India. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में कंपनियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने पर निगरानी व प्रतिबंध लगाता है। इसने कुछ समय पहले गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया था।

CCI के कार्य
- ① स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना
- ② कंपनियों के एकाधिकार को रोकना
- ③ विदेशी कंपनियों को भारतीय कानून पालन करने के लिए बाध्य
- ④ भारतीय बाजार में विरूपता को रोकना

चुनौती
- ① CCI एक कार्यकारी संगठन है कानूनी प्रभाव सीमित
- ② कंपनियाँ आदेश की अवहेलना करती
- ③ शक्तियों का अभाव

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

उपाय
→ एक अधिकरण की स्थापना
→ खुद की प्रशासनिक मशीनरी
→ विदेशी कंपनियों को डाटा स्थानीकरण करने के लिए कहना ताकि CCI अच्छे से जांच कर सके

विभिन्न विभागों में समन्वय → finance ministry
→ CCI
→ ED
→ I.T

अतः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अभी और सक्रिय होकर स्वस्थ्य बाजार प्रतिस्पर्धा तैयार करनी चाहिए।

drishti | दृष्टि The Vision

8. सरकारी कार्यों में ई-गवर्नेंस के उपयोग से दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार हुआ है। इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा डालने वाली कमियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

E-governance has brought about greater effectiveness, transparency, and accountability in government functions. Highlight the shortcomings that hinder the improvement of these features. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रशासन मे ICT का उपयोग ई-गवर्नेंस है जो प्रशासन मे सुलभता पारदर्शिता, ईमानदारी और तेजी लाता है वर्तमान डिजिटल इंडिया का यह आधार है

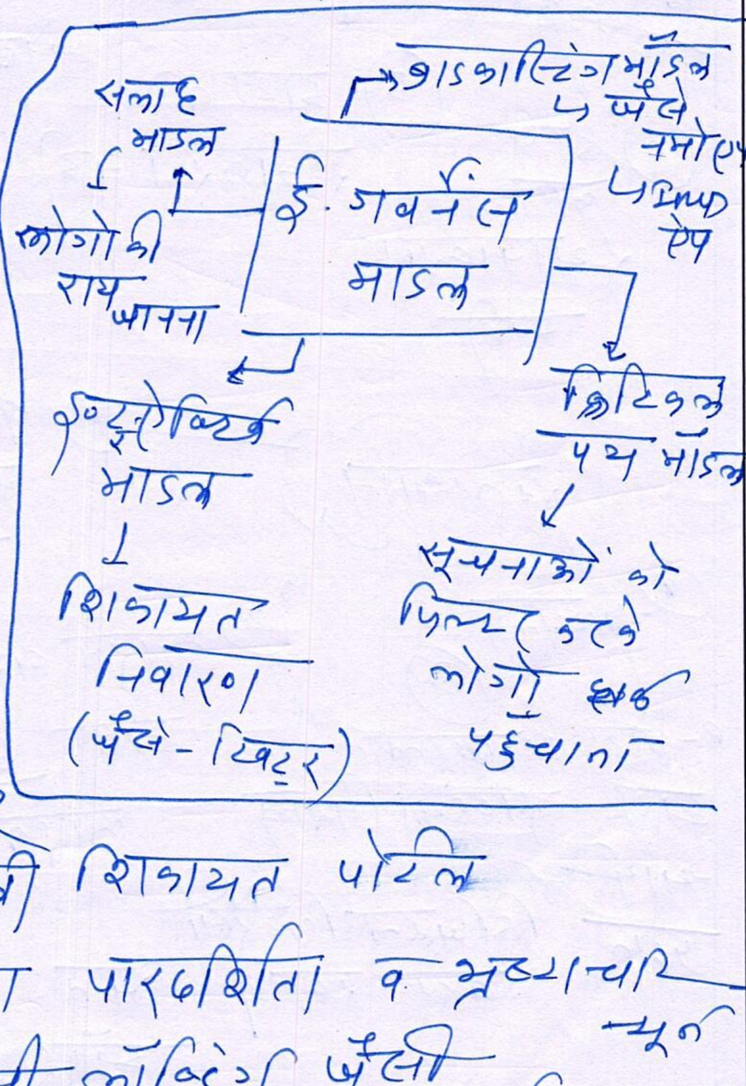

लाभ

① शासन और नागरिक मे दूरी न्यून
जैसे → कोविन एप
→ डिजीलॉकर
→ मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल

② DBT द्वारा पारदर्शिता व भ्रष्टाचार न्यून

③ UPI मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं मे पारदर्शिता

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(4) इण्डिया स्टैक, ONDC, UPI, आदि डिजिटल इण्डिया के स्वप्न को पूरा।

प्रमुख कमियाँ

(1) डिजिटल डिवाइड तथा डिजिटल असाक्षरता

(2) महिलाओं के पास मोबाइल नहीं (42%)

(3) डाटा का एकीकरण नहीं
- केन्द्र → NIC
- राज्य → SDC

(4) डाटा का स्थानीकरण नहीं

(5) विदेशी सेवर पर आश्रित

समाधान

(1) IIndARC ने राज्य व केन्द्र के डेटा मिलाने को कहा

(2) भारत सरकार भारत नेट द्वारा 6.50 लाख गांव में फाइबर

(3) डिजिटल इण्डिया मिशन → डिजिटल लिटरेसी बढ़ रहा।

(4) न्यायालय → e-कोर्ट द्वारा कार्य प्रणाली

अतः एक भारत और श्रेष्ठ भारत में ई-प्रशासन एक प्रमुख व महत्वपूर्ण साधन है।

9. SCO को प्रायः चीन-रूस सहभागिता हेतु एक मंच के रूप में देखा जाता है। संगठन के भीतर भारत के सामरिक हितों के लिये इस साझेदारी के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The SCO is often seen as a platform for Sino-Russian collaboration. Discuss the implications of this partnership for India's strategic interests within the organization. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

SCO की स्थापना 1996 मे चीन व रूस के सहयोग से सेन्ट्रल एशिया मे अपने निहितार्थों के लिए की गई। वर्तमान मे इसे अमेरिका तथा पश्चिम राष्ट्र की निगाह से देखते है

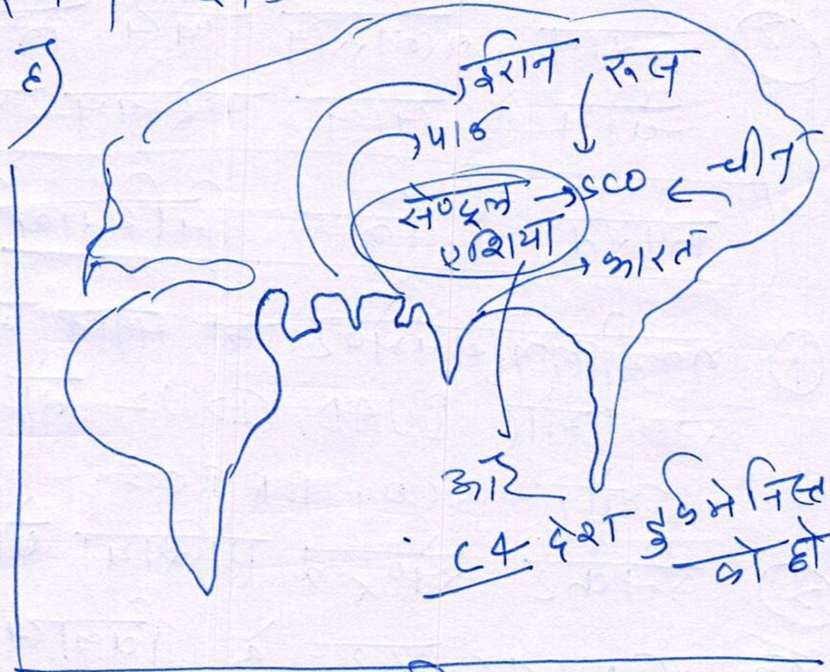

भारत व पाक 2017 मे इसके सदस्य बने तथा अभी हाल मे ईरान व बेलारूस भी इसके सदस्य बने।

भारत अपनी मल्टी अलायनमेन्ट की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है

चीन-रूस सहभागिता मंच के रूप में देखने के कारण →

1. वर्तमान मे चीन का दक्षिणी चीन सागर मे शक्तिशाली उभार तथा रूस-यूक्रेन युद्ध ने इस मंच को पश्चिम दुनिया मे संदेह बना दिया।
2. ईरान, बेलारूस जैसे देश रूस व चीन के साथ पश्चिम मे शंका।

भारत के लिए निहितार्थ

1. मल्टीअलायनमेंट की नीति मे सहायक एक ओर QUAD, I2U2 तो दूसरी ओर SCO, BRICS
2. कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी मे
3. INSTC रूट के विकास मे
4. चीन व पाक को काउंटर करने मे
5. अफगानिस्तान से आतंकवाद को रोकने मे।

अतः भारत के विश्वशक्ति बनने के लिए जरूरी है वह अपने सामरिक प्रभाव को हर जगह बढ़ाए इसीलिए SCO आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

10. भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The Indian diaspora significantly influences the political and economic landscapes of the United States and European countries. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत का विदेशों में लगभग 35 मिलियन डायस्पोरा है जो दुनिया में सर्वाधिक है यह सॉफ्ट पावर के निर्माण में सहायक है ऐसे में USA और यूरोप में उनका महत्व →

राजनीतिक परिदृश्य में :-

1. भारत-अमेरिका की 2008 की सिविल परमाणु डील में डायस्पोरा का सहयोग
2. अमेरिका का समोसा कॉकस समूह (जिसमें रो खन्ना) भारतीय हितों की पैरवी
3. भारत का पंजाबी समूह कनाडा में प्रभावी।
4. यूरोप के ब्रिटेन में भारतीयों की राजनीति में सक्रियता तथा भारत समर्थित का माहौल

आर्थिक परिदृश्य में

① अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ोत्तरी जो अब $120 बिलियन पहुँच गया रेमिटेंस में अग्रणी भूमिका

② यूरोप के साथ FTA में सहायता

③ ब्रिटेन के साथ FTA में भारतीय लोगों की क्रियाशीलता तथा सरकार पर दबाव

चुनौतियाँ
→ वर्तमान का पन्नू मामला
→ खालिस्तानी समस्या
→ भारत के ऊपर IPR चुराने का आरोप — USPCL Report 301
→ मानवाधिकार व अल्पसंख्यक दमन का आरोप
→ FTA में डाइरोलैनिटरी समस्या

अतः सोफ्ट पावर बढ़ाने के डायस्पोरा अति महत्वपूर्ण है। यह भारत को विश्व शक्ति बनने में सहायक है।

11. भारत का संविधान एक गतिशील, जीवंत दस्तावेज़ है, जिसे प्रगतिशील समाज के साथ अनुकूलन और विकास के लिये अभिकल्पित किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्द) 15

The Constitution of India is a dynamic, living document, designed to adapt and evolve with a progressive society. Illustrate with reference to right to life and personal liberty. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत का संविधान समय के साथ चलने और आकांक्षाओं की पूर्ति ~~निर्माण~~ करने मे सुसंगत है। इसमे अनु. 12-35 तक अधिकारो का वर्णन किया गया है

अनु.21 ~~अनु~~

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सहित →

→ भारत मे विधि की स्थापित प्रक्रिया पाई जाती है

→ परंतु 1973 के केशवानंद भारती वाद के बाद यह उचित प्रक्रिया मे तब्दील हुई। → बेसिक स्ट्रक्चर

→ 1978 के मेनका गांधी मे उचित प्रक्रिया स्थापित अनु.21 मे हुई।

अनु.21 एक वृहत अनुच्छेद है यह अपने अंदर वर्तमान मे कई आयाम समेटे हुए है।

मेनका गांधी केस मे न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार मे कोई पशु का अधिकार नही है, यहाँ मानव की गरिमा भी आवश्यक है। तब से अब तक न्यायालय ने कई वाद मे इसका विस्तार किया जैसे→

1. मेनका गांधी वाद → पासपोर्ट का अधिकार
2. एमसी मेहता वाद → स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
3. नवीन जिन्दल वाद
↳ तिरंगा फहराने का अधिकार

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) बाबा रामदेव वाद
↳ निद्रा का अधिकार

(5) डा गुप्ता वाद ↳ निशुल्क व निष्पक्ष न्याय का अधिकार

(6) नवतेज सिंह जौहर वाद → विवाह व संबंध व्यक्ति के निजी जीवन

(7) शक्तिवाहिनी वाद
↳ अपने मनपसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार

कुछ चुनौतियाँ
→ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत
→ न्यायिक विधायन व अति सक्रियता
→ कार्यपालिका से टकराव, अध्यादेश में कटौती
→ PIL का दुरुपयोग

अतः न्यायिक संयम के साथ जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के सार्वभौमिक व सर्वांगमुखी विकास में सहायक है

12. जेंडर न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों की सहायता से स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

The concept of gender justice is inherently embedded in the Indian Constitution. Explain with the help of relevant constitutional provisions and case laws. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत का संविधान एक प्रगतिशील व आधुनिक दस्तावेज है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों का विशेष सम्मान किया गया। ऐसे में जेंडर न्याय इसका आधार है -

संवैधानिक प्रावधान →

अनु. 14 → कानून के शासन व सभी को समान

अनु. 15/16 → महिलाओं के साथ भेदभाव की मनाही

अनु. 39 → समान कार्य के लिए समान वेतन

73 वें & 74 वें संशोधन
↳ पंचायतों में महिला आरक्षण

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

106 वां संशोधन → LS4 में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व

निर्णय/विधियों → :

(1) शाहबानो व शायराबानो वाद में मुस्लिम महिला के लिए समान कानून

(2) शक्तिवाहिनी वाद में न्यायालय ने महिला को जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता

(3) संपत्ति में समान हिस्सा तथा पुरुष व लड़की को समान अधिकार

(4) विशाखा वाद (1996) में कार्यस्थल पर यौन हिंसा को रोकने के लिए दिशानिर्देश

(5) 2020 के निर्णय में महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(6) यंग लॉयर केस मे महिलाओं को मंदिर प्रवेश → शनि मंदिर
→ केरला का मंदिर

इसके बाद सरकार ने

हिन्दू उत्तराधिकार अधि०, POSH अधि०, दहेज प्रतिषेध अधि०, बाल विवाह निषेध अधि०, अनैतिक व्यापार रोक अधि० आदि का निर्माण किया है तथा महिला सशक्तीकरण व लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

13. भारत में प्रभावी नीतियों को आकार देने और कार्यान्वित करने में नागरिक समाज संगठनों के योगदान का अन्वेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Explore the contribution of civil society organizations in shaping and executing effective policies in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नागरिक समाज स्वतंत्र, आर्थिक व राजनीतिक लाभ से दूर, समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाला समूह है।

नागरिक समाज स्वैच्छिक व पंजीकृत दोनों हो सकते हैं

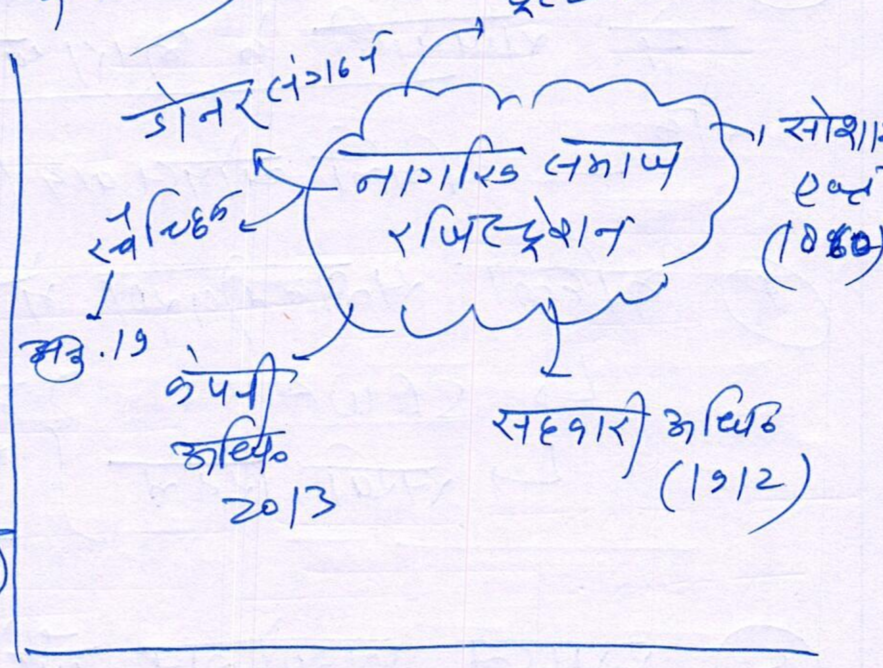

योगदान →

① MKSS (मजदूर किसान शक्ति संगठन)
↳ RTI विकास में
↳ पारदर्शिता प्रशासन में

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(2) ADR जैसे समूह राजनीति में उच्च नैतिकता व पारदर्शिता
जैसे → हाली का ADR v/s UOI केस मे इलेक्टोरल बाण्ड पर निर्णय

(3) जनप्रहरी संस्था की लिली थोमस ने राजनीति के अपराधीकरण पर रोक
↳ लिली थोमस वाद (2013)

(4) महिला सशक्तीकरण मे
↳ SEWA
↳ सखी रिटेल
} महिलाओं को सूक्ष्म वित्तीयन का आर्थिक निर्भर

(5) स्माइल फाउण्डेशन जैसे समूह बच्चे के लिए कार्य

(6) टाटा ट्रस्ट जैसे संगठन गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व अस्पताल के विकास में सहायता

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

→ ① स्वैच्छिकतावाद का अभाव
↳ रोजगार का साधन समझते NGO को।

→ ② विदेशी फंडिंग तथा फिर राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप
↳ किसान आंदोलन पर खालिस्तानी के चन्दा का आरोप

→ ③ मानवाधिकार का हनन कहकर सरकार व सेना पर दबाव जैसा J&K मे दिखता

सुधार के उपाय

→ ① FCRA कानून सख्त
→ ② प्रत्येक NGO की ऑडिट
→ ③ विदेशी फंडिंग पर नजर
→ ④ सफल लोगो को NGO निर्माण के प्रोत्साहन

अत: नागरिक समाज, प्रशासन व सरकार तीनो मिलकर भारत के 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकते है

drishti | दृष्टि The Vision

14. 'भारतीय न्यायपालिका पुरुष प्रधान है।' इस कथन के आलोक में न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिये। साथ ही सुधारात्मक उपाय संबंधी सुझाव भी प्रदान कीजिये। (250 शब्द) 15

'Indian judiciary is a male dominated affair.' In the light of this statement discuss the issues related to the representation of women in judiciary. Also, suggest remedial measures. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

जेंडर जस्टिस प्रत्येक जगह जरूरी है भारत की न्यायपालिका ने अभी तक स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य किया परंतु प्रतिनिधित्व व जेंडर जस्टिस वहाँ भी जरूरी है।

आँकड़े → SC → 34 जज में 3
→ HC → 10-11%
→ वकील में → 10-20%

नेशनल डाटा ग्रिड

न्यायपालिका में महिलाएँ न होने के कारण →

① पितृसत्तात्मक व्यवस्था, महिलाओं को न्याय के अनुकूल नहीं मानते

② लॉ व वकालत का करियर लम्बा होता तो महिलाएँ यह करियर नहीं चुनती।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(3) न्यायालय में महिला आरक्षण नहीं
(4) भाई-भतीजावाद के कारण उच्च अच्च महिलाओं को नहीं चुनते (कॉलेजियम में)

इससे उत्पन्न चुनौती

(1) न्याय में सर्वसमावेशी व संतुलित दृष्टिकोण का अभाव।
↳ महिला पक्ष नहीं
(2) महिला के साथ अवसर की समानता का अभाव
(3) न्यायालय में महिला के अनुकूल वातावरण नहीं

महिला प्रतिनिधित्व के लाभ

(1) महिला का दृष्टिकोण न्याय में
(2) महिला कैदियों को गवाही व अपनी बात रखने में सुलभता
(3) जेंडर जस्टिस की स्थापना
(4) संविधान के अनु. 39 का स्थापित होना

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सुधारात्मक उपाय

① लॉ की शिक्षा में महिलाओं को प्रोत्साहन

② AIJS की स्थापना तथा महिला आरक्षण

③ महिला वकीलों व न्यायाधीशों के लिए अवसंरचना निर्माण यथा- शौचालय, क्रैच हाउसों

④ कॉलेजियम में महिला को रखना

⑤ जागरूकता बालिकाओं में

अतः जेंडर पैरिटी समय की मांग है। यह सतत विकास लक्ष्यों (SDG-5) में सहायक है तथा संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की मांग करता है।

15. भारतीय संविधान एकात्मकता का भाव रखता है यद्यपि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों की सुदृढ़ता एवं स्वतंत्रता से समझौता किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

Indian Constitution comes with a unitary bias. However, that does not mean that the Constitution makers took anything away from strong and independent states. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत मे कनाडा की तरह संघवाद अपनाया गया है जहाँ शक्तियों का झुकाव केन्द्र की तरफ है परंतु इसने राज्यों को कोई अधीनस्थ इकाई नही बल्कि स्वतंत्र इकाई माना है

संघवाद

- अमेरिका
  ↳ Federal
- स्विट्जरलैंड
  ↳ Confederal
- भारत
  ↳ Unitary

संघवाद की विशेषता

→ शक्ति का स्पष्ट विभाजन
→ संविधान सर्वोच्च
→ स्वतंत्र न्यायपालिका

एकात्म

→ एकल न्यायपालिका
→ एकल नागरिकता
→ राजकोषीय संघवाद केन्द्र के पक्ष मे।

(एकात्मकता का भाव)

① एकल न्यायपालिका, भारत में SC सर्वोच्च है।

② राज्यकोषीय संघवाद के लिए राज्य केन्द्र पर निर्भर (अनु. 280)

③ राज्यपाल जो राज्य में शासन प्रमुख केन्द्र से नियुक्त

④ अनु. 352, 356, 360, आपातकाल का प्रावधान

⑤ दिशानिर्देश (Directories by Centre) व अनु. 252, 253, 254

⑥ एकल नागरिकता, राज्य की अलग नही जैसी अमेरिका में

परंतु यह उपर्युक्त प्रावधान भारत के भूगोल व चुनौतियों को देखकर रखे गए थे। डॉ. अम्बेडकर ने पहले ही कहा था भारत

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

का संघवाद कोई समझौते का परिणाम नहीं है अमेरिका की तरह।

(राज्यों की पृथकता व स्वतंत्रता)

① सूचियों – राज्य / संघ का स्पष्ट प्रावधान तथा शक्तियों का विभाजन

② राज्यों को कर लगाने व खुद का प्रशासन करने का अधिकार

③ खुद की प्रशासन सेवा (PCS)

④ कर का स्पष्ट विभाजन स्वतंत्रता व निष्पक्षता से (अनु. 280)

⑤ राज्य की विधि सर्वोच्च राज्य में तथा सिविल कानून बनाने का अधिकार

अतः वर्तमान समय सहकारी व प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का है। जहाँ राज्य व केन्द्र साथ-2 आगे बढ़कर विकसित भारत का निर्माण करें।

16. राज्यसभा की उपेक्षा करने के लिये कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न करता है। इस संवैधानिक चिंता के समाधान से संबंधित उपायों के सुझाव प्रदान कीजिये। (250 शब्द) 15

Categorization of certain bills as Money Bills to bypass Rajya Sabha raises constitutional concerns. Suggest ways to tackle this constitutional concern. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉण्ड केस में इसके धन विधेयक में शामिल करने पर चिंता जाहिर की थी। ऐसे में धन विधेयक के प्रावधान —

धन विधेयक → अनु. 110

↳ प्रक्रिया → अनु. 109

लोकसभा अध्यक्ष घोषित

→ लोकसभा में प्रस्तुत

→ राष्ट्रपति की अनुमति पर

→ राज्यसभा सिर्फ चर्चा कर सकती है - संशोधन या निरस्त नहीं

→ राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लौटाना होगा वरना पास माना जाएगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं

→ राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता।

(संवैधानिक चिंता) → धनविधेयक घोषित करने पर

संविधान में कर लगाना, उत्पादन करने, संचित निधि पर भारित आदि के लिए धन विधेयक का प्रावधान किया गया था। ताकि कार्यपालिका को चुनौती उत्पन्न न हो तथा वह धन आवरण में जनता के विश्वास को बनाए रखे।

(परंतु)

(1) कार्यपालिका ऐसा करके राज्यसभा में वोटिंग को रोकना चाहती थी

जैसे → आधार कार्ड मामले

→ इलेक्टोरल बाण्ड मामले

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

इन दोनों को सरकार ने धन विधेयक में शामिल किया

(2) चूँकि कार्यपालिका/सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो वह ऐसा करके उसे पास करवाना चाहती थी

समाधान के उपाय

→ लोकसभा अध्यक्ष को तटस्थता व निष्पक्षता के साथ धन विधेयक घोषित करना चाहिए

→ स्पष्ट लोकसभा नियम का निर्माण करना चाहिए।

→ एक समिति का निर्माण जो धन विधेयक का वर्गीकरण करें।

अतः यह व्यवहार राजनैतिक प्रतीत होते है संवैधानिक नहीं। इसलिए नैतिक संयम आवश्यक है।

17. ‘भारतीय संविधान अंशत: पश्चिमी देशों के संविधान से गृहित दस्तावेज़ है।’ समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

‘Indian Constitution is a bag of borrowings.’ Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को तैयार हुआ। इसने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन शामिल है इस पर एक आरोप उधार होने का है —

पश्चिमी देशों से उधार का आरोप → कारण

1. भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से
2. 1935 के भारत शासन अधि. का 75% भाग एक जैसा लिया
3. अमेरिका से → अधिकार, न्यायपालिका, राष्ट्रपति
4. जर्मनी → आपातकाल

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(5) आस्ट्रेलिया → समवर्ती सूची

(6) रूस → मौलिक कर्तव्य

(7) जापान → विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

परंतु यह आरोप पूर्णत: सत्य नहीं है डा. अंबेडकर ने कहा था दुनिया से अच्छे प्रावधानों को लेना कोई बुरी बात नहीं है भारत ने अपने हिसाब से अपने देश के अनुरूप संविधान तैयार किया ~~जैसे~~

(1) भारत ने संघवाद न तो अमेरिका की तरह और न ही स्विटज़रलैण्ड की तरह लिया।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(2) भारत ने अधिकारों के साथ निदेशक तत्व रखे।

(3) सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण का प्रावधान

(4) गणतंत्र को अपनाया न कि ब्रिटेन तरह संवैधानिक राजतंत्र को

आज 18 वी लोकसभा के चुनाव तथा 106 संविधान संशोधन के बाद भी हमारा संविधान जीवंत व समय के अनुकूल है। यह 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाओं को पूरा कर रहा है।

18. प्रौद्योगिकी के संबंध में जागरूकता का अभाव या अपर्याप्त ज्ञान समाज में डिजिटल विभाजन का कारण बनता है। स्पष्ट कीजिये कि यह भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। (250 शब्द) 15

Lack of technological awareness or knowledge leads to a digital divide in society. Explain how it adversely effects the education and health sector of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

औद्योगिक क्रांति 4.0 के समय डिजिटल ज्ञान भविष्य के भारत निर्माण में सहायक है। यह ई-प्रशासन का आधार है।

डिजिटल विभाजन का

कारण → प्रौद्योगिकी के संबंध में अभाव

1. भारत की बड़ी आबादी अभी शिक्षित नहीं (साक्षरता ~ 77%)
2. प्रौद्योगिकी को लेकर जेनरेशन गैप, वृद्ध लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते
3. गांवों में नेट व मोबाइल अवसंरचना का अभाव

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

शिक्षा को प्रभावित

कोविड के बाद से e-शिक्षा प्रमुख से उभरी है परंतु प्रौद्योगिकी के संबंध में ज्ञान के अभाव में यह अनेक चुनौतियाँ पेश कर रही

चुनौतियाँ →
- जनजातियों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं।
- टीचर को प्रौद्योगिकी अनुभव नहीं इसलिए स्मार्ट क्लास में बाधा
- कौशल व क्षमता का अभाव → बच्चे अनभिज्ञ गूगल से

स्वास्थ्य को प्रभावित

→ टेलीमेडिसन और e-चिकित्सा के दौर में तकनीक अति आवश्यक है

परंतु चुनौतियाँ →
1. तकनीक महंगी
2. सभी तक पहुँच नहीं
3. लोग महंगी तकनीक से बचते
4. AI, Robotic Surgery के बारे में लोगों को पता नहीं

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

दूर करने के सुझाव

6.5 लाख

(1) भारत नेट जैसी योजनाएँ गाँवों में पहुँचकर विद्यार्थी जिससे नेट का विस्तार

(2) डिजिटल इंडिया मिशन डिजिटल लिटरेसी में सहायक

(3) ऑनलाइन शिक्षा क्रांति है वर्तमान में

(4) शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल offline Online

(5) चिकित्सा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन → डाटा एकीकृत

(6) नेशनल हेल्थ डाटा →

(7) CRISPR Cas 9 जैसी नवाचारित स्वास्थ्य जीन प्रौद्योगिकी का विस्तार

अंततः सरकार नागरिक समाज के साथ इसे दूर कर सकती है तथा NEP 2020 के प्रावधानों को लागू कर सकती है

19. नाटो का विस्तार एवं अमेरिकी-यूरोपीय सामरिक सहयोग का सुदृढ़ीकरण भारत के हितों को संपुष्ट करता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

India's interests are well-served by NATO's growth and the stronger U.S.-Europe strategic cooperation. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नाटो की स्थापना (1949) के समय से ही इसके अर्थात अमेरिका और यूरोप के संबंध गहरे होते गए। वर्तमान यूक्रेन-रूस संघर्ष मे यह अनेक चुनौतियों का सामना भी कर रहे ऐसे मे भारत का दृष्टिकोण आवश्यक है।

अमेरिका-यूरोप सामरिक सहयोग से भारत को लाभ →

① भारत व यूरोप व अमेरिका तीनो की साझी सुरक्षा चिंता चीन है। ऐसे मे क्वाड दक्षिणी चीन सागर और हिन्द प्रशांत में भारत के लिए आवश्यक है साथ मे AUKUS की भरती है।

UK, USA, Australia

drishti | दृष्टि The Vision

(2) भारत को अमेरिका के माध्यम से यूरोप का सहयोग तथा भारत की FTA नीति सफल हो सकती।

(3) भारत के मल्टीएलायनमेंट नीति मे सहायक।

(4) IMEC जैसे रूट का सफल क्रियान्वयन तथा चाइना के OBOR का प्रतिसंतुलित

(5) भारतीय PM की वर्तमान यूरोप यात्रा यथा ऑस्ट्रिया, पोलैण्ड और फिर यूक्रेन भारत के संदर्भ यूरोप मे महत्व का द्योतक है।

(6) भारत को NSG की सदस्यता मिल सकती

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

(1) रूस को संतुलित करने में

(2) भारत का SCO व BRICS का सदस्य पश्चिम दुनिया में भारत को शक की निगाह से देखना

(3) चीन क्वाड को हिन्द प्रशांत में नाटो मानता

(4) वर्तमान इजरायल - हमास जंग में भारत के पक्ष लेने पर दबाव

(5) पर्यावरण वार्ताओ व WTO वार्ताओ में यूरोप व अमेरिका भारत को प्रतिसंतुलित व विरोध करते।

अतः भारत वर्तमान में अपने राष्ट्रीय हितो को आगे रखते हुए एक ओर रूस से तेल ($60 Billion) खरीद रहा तो दूसरी ओर अमेरिका, यूरोप के साथ खड़ा है (क्वाड, IMEC) एवं ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है

20. पर्यावरण संरक्षण एवं समुद्री सुरक्षा संवर्द्धन में IMO (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Role of IMO (International Maritime Organisation) in protecting environment and enhancing maritime safety and security cannot be overstated. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वर्तमान मे जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर और सागर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं मे IMO जो समुद्र संगठन है तथा समुद्री रक्षा व सुरक्षा मे महत्वपूर्ण है

IMO के कार्य

→ वर्तमान की High Seas Treaty को लागू करने

↳ जैवविविधता को बचाना

→ चक्रवात के नामकरण मे सहायक

↳ इसके 6 रीजनल कार्यालय है एक हिन्दमहासागर मे है जिसकी अध्यक्षता भारत करता |

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ UNCLOS के क्रियान्वयन मे

→ (Hope Spot) होप स्पोट को

जैवविविधता व महासागर की पारिस्थितिकी है उसके संरक्षण में

→ यह ग्लेशियर से बढ़ते जलस्तर के कारण द्वीपीय देशों को चेतावनी देता।

→ यह लंदन अभिसमय को समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया उसकी निगरानी।

→ एल नीनो व ला नीना के प्रभाव का अध्ययन

→ Oil spill की घटना पर निगरानी

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अतः IMO, WMO के साथ मिलकर जलवायु, मौसम व समुद्र तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है यह SDG लक्ष्य-14 (जल पर जीवन) को पाने का प्रयास कर रहा।

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)